

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों के अधिष्ठान मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-2250-800-21-00-जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों अधिष्ठान मद में प्राविधानित धनराशि रु0 72.07 लाख (₹ बहत्तर लाख सात हजार मात्र) के सापेक्ष पूर्व में शासनादेश संख्या-814/XVII-3/14-02(1)/2014, दिनांक 25.09.2014 द्वारा निर्गत ₹ 37.86 लाख (₹ सैतीस लाख छियासी हजार मात्र) के अतिरिक्त अवशेष धनराशि में से ₹ 9.16 लाख (₹ नौ लाख सोलह हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
4. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
5. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।



7. बी0एम0-08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाएँ नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अबचन मदों को आहरण-विवरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जाये कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी, न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत मदें यथा फर्नीचर, साज-सज्जा, उपकरण क्रय विद्युत प्रभार, स्टेशनरी/कम्प्यूटर स्टेशनरी, पेट्रोल/डीजल आदि में मितव्ययिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 2250-00-800-21-00-जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान के मद के नामे डाला जायेगा।
17. यह आवंटन अनुदान संख्या-15 के अलोटमेंट आई डी संख्या-S1503150123, दिनांक 10 मार्च, 2015 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न- यथोक्त।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- 278/XVII-3/15-02(01)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
4. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादू।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)  
संयुक्त सचिव।